[2015] 1 एस. सी. आर. 55

भारत केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और अन्य

बनाम

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एससी/एसटी कर्मचारी वेल्फेयर एसोसिएशन एंड अन्य

(सिविल अपील संख्या 209 /2015)

09 जनवरी, 2015

[न्यायाधिपति जे. चेलामेश्वर और न्यायाधिपति ए. के. सिकरी]

सेवा कानून: आरक्षण - चयन द्वारा पदोन्नति में - एक अधिकारी रैंक/ग्रेड से ग्रेड में अगले रैंक तक - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए - अनुमति - धारित: कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1.11.1990 और 13.81997 के आधार पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार (जिसे बैंक द्वारा अपनाया गया था) द्वारा समूह-ए पदों के भीतर पदोन्नति के मामलों में जारी किया गया है, जिसमें 5,7001 रुपये प्रति माह का अंतिम वेतन है। यानी स्केल VII और उससे ऊपर, आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है - हालाँकि, स्केल-I से स्केल VI तक पदोन्नति में आरक्षण पर कोई रोक नहीं है।

न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया

न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया और अभिनिर्धारित किया-

1. कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1.11.1990 में, समूह-ए पदों के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था,

जिसका अंतिम वेतन रु. 5,700/- प्रति माह. कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.8.1997 द्वारा, पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मौजूदा प्रावधान को 15-11-1997 से आगे जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, इस ज्ञापन ने एससी/एसटी कर्मचारियों के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण के लिए कोई नया प्रावधान नहीं किया। इन दोनों कार्यालय ज्ञापनों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, पदोन्नति के मामले में इस तरह के आरक्षण के किसी अन्य प्रावधान या नियम के अभाव में, यह यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रुप-ए पदों के भीतर 5,700/- रुपये प्रति माह के अंतिम वेतन तक पदोन्नति में आरक्षण था। [पैरा 27, 31 और 32) (79-ई; 81-बी-सी, डी-ई)

2. सार्वजनिक उद्यम विभाग ने दिनांक 08-11-2004 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था जिसमें आरक्षण के प्रयोजनों के लिए 5,700/- रुपये की वेतन सीमा का उल्लेख 18,300/- रुपये (पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग) के रूप में किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न का पालन कर रहे हैं, उनकी मौद्रिक सीमा 20 रुपये तय की गई थी, (01-01-1996 से, यानी 5 वें केंद्रीय वेतन आयोग से)। अपीलकर्ता बैंकों में उक्त वेतन सीमा तभी प्राप्त होती है जब कोई अधिकारी स्केल-VII तक पहुँच जाता है। एक फोर्टिओरारी के रूप में, पदोन्नति के मामले में कोई आरक्षण नहीं की नीति केवल स्केल-VII और उससे ऊपर पर लागू होती है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से इस प्रकार है कि जहां तक स्केल-I से स्केल-II, स्केल-II से स्केल-III, स्केल-III से स्केल-IV, स्केल-IV से स्केल-V, सीली से स्केल-VI तक पदोन्नति की बात है चिंतित हैं, आरक्षण देना है. इसलिए, अपीलकर्ता बैंक उपरोक्त ज्ञापन के तहत आपत्ति नहीं उठा सकते हैं और स्केल-VI तक पदोन्नति करते समय एससी/एसटी कर्मचारियों के पक्ष में आरक्षण से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए, स्केल-I से स्केल-VI तक पदोन्नति करने के लिए एससी/एसटी कर्मचारियों के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। [पैरा 35 और 36) (82-डी-एफ; 83-बी]

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ 1992 (2) सप्ल एससीआर 454 = 1992 (3) सप्ल एससीसी 217, भारत संघ और अन्य आदि बनाम वीरपाल सिंह चौहान और अन्य 1995 (4) सप्ल एससीआर 158 =1995 (6) एससीसी 684; नेशनल फेडरेशन ऑफ एस.बी.आई एंड अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1995(2) एससीआर 748 =1995 (3) एससीसी 532; प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक (अब असम ग्रामीण विकास बैंक के रूप में जाना जाता है) और अन्य बनाम बृजलाल दास 2009 (2) एससीआर 299 = 2009 (3) एससीसी 323 हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति कर्मचारी महासंघ और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश समान वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ और अन्य 2013 (9) एससीआर 384 =2013 (10) एससीसी 308; रोहतास भांखर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2014 (8) एससीसी 872; एम.नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2006 (7) पूरक। एससीआर 336 =2006 (8) एससीसी 212 - संदर्भित।

वाद कानून संदर्भित

1992(2)पूरक एस सी आर 454	संदर्भित	पैरा 8
1995(4)पूरक एस सी आर 158	संदर्भित	पैरा 9
2006(7)पूरक एस सी आर 336	संदर्भित	पैरा 11
1995(2)एस सी आर 748	संदर्भित	पैरा 18
2009(2)एस सी आर 299	संदर्भित	पैरा 18
2013(9)एस सी आर 384	संदर्भित	पैरा 21
2014(8)एस सी सी 872	संदर्भित	पैरा 22

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 209/2015

1998 की रिट अपील संख्या 342 में मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय और आदेश दिनांक 09-12-2009 से।

साथ

अवमानना याचिका (सी) संख्या 320 2010 में एसएलपी (सी) संख्या 5046 2010 में

सिविल अपील संख्या 210, 211, 212 और 213/2015

सी.एस. वैद्यनाथन, राजू रामचन्द्रन, जयदीप गुप्ता, जे.एस. अत्री, ओ.पी. गग्गर, राजेश सिंह, नवीन आर. नाथ, ललित मोहिनी भट्ट, राजीव नंदा, डॉ. कृष्ण सिंह चौहान, अजीत कुमार एक्का, रवि प्रकाश.चंद किरण, मुरारी लाल, विद्या सागर, जेनिफर जॉन, के केयाली सरकार, सत्यजीत ए.देसाई,अनघा एस.देसाई, ए.सुब्बा राव, लक्ष्मी रमन सिंह, सी.के.चंद्रशेखर, एस.आर.सेतिया, विकास बंसल, रेखा पांडे, डी.एस महरा, हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलकोट, के. राजीव, मुकुल कुमार उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधिपति ए.के. सिकरी

1. अनुमति स्वीकृत। कार्यान्वयन और हस्तक्षेप आवेदनों की अनुमति है।

2. इन अपीलों में विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह एक संकीर्ण परिसर के भीतर है और स्पष्ट है, हालांकि साथ ही यह हमारे सामने मौजूद पक्षों के लिए मौलिक महत्व का है। यह अपीलकर्ता बैंकों में अधिकारी ग्रेड/स्केल में पदोन्नति में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण के नियम से संबंधित है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता बैंक, जो वैधानिक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, एससी और एसटी कर्मचारियों के आरक्षण से संबंधित केंद्र सरकार के लागू दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं, जहां तक लिपिक ग्रेड से अधिकारी ग्रेड में उनकी पदोन्नति का

संबंध है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि क्या एक अधिकारी ग्रेड/स्केल से दूसरे ग्रेड/स्केल में पदोन्नति में कोई आरक्षण है, जब ऐसी पदोन्नति चयन के आधार पर की जाती है। अपीलकर्ता बैंकों के अनुसार, 5,700/- से अधिक मूल वेतन वाले पदों/मानों पर क्लास ए (क्लास- I) में पदोन्नति के लिए आरक्षण का कोई नियम नहीं है और कार्यालय ज्ञापन के रूप में जारी किए गए संबंधित निर्देशों में, केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति के लिए विचार करने के तरीके में रियायत प्रदान की जाती है। अन्यथा कहें तो, बैंकों की स्थिति यह है कि पदोन्नति के लिए आरक्षण का कोई नियम नहीं है और पदोन्नति के लिए इन श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों की उम्मीदवारी पर शिथिल मानकों के आधार पर विचार किया जाना है। प्रतिवादी, जो अपीलकर्ता बैंकों के एससी/एसटी कर्मचारी संघ हैं या ऐसी श्रेणियों से संबंधित व्यक्ति हैं, बैंकों द्वारा उठाए गए उपरोक्त रुख पर विवाद करते हैं। उनके अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र स्पष्ट रूप से इस तरह के आरक्षण का प्रावधान करता है।

3. दिलचस्प बात यह है कि दोनों पार्टियां अपना-अपना पद लेने के लिए ओ.एम. पर भरोसा करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 13-08-1997 (जिसे, निश्चित रूप से, अन्य संबंधित कार्यालय ज्ञापनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए)। इस प्रकार इन अपीलों का परिणाम उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13-08-1997 को दी जाने वाली व्याख्या पर निर्भर करेगा। चूंकि बैंक 09-12-2009 को दिए गए मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं, जिसमें कई रिट अपीलों का निपटारा किया गया था, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, उपरोक्त परिपत्र की व्याख्या एससी/एसटी कर्मचारियों के पक्ष में गया है।

4. इससे पहले कि हम मुद्दे के मूल बिंदु पर लौटें और अपना उत्तर दें, हम उन ऐतिहासिक तथ्यों को संक्षेप में दोहराना उचित समझते हैं जिनके कारण यह वर्तमान मामला सामने आया है।

5. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता बैंक, जो वैधानिक बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, समय-समय पर सरकार द्वारा जारी की गई भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए, ऐसे प्रत्येक बैंक की प्रमोशन नीति इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान करती है। यह भी सामान्य ज्ञान की बात है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार वित्तीय संस्थानों/बैंकों के लिए आरक्षण पर नीति तैयार करने के लिए नोडल मंत्रालय है। उदाहरण के लिए, विनियम 1.1 यूको बैंक के अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति निम्नलिखित तरीके से ऐसा प्रावधान करती है:

"बैंक में अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति अधिकारी सेवा विनियमों के तहत समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में तैयार की गई है।"

उपरोक्त पदोन्नति नीति के विनियमन को यहां उद्धृत करना भी प्रासंगिक होगा। यह विनियम निम्नलिखित पाठ्य बनाता है

> "22. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के अधिकारियों के लिए रियायतें/छूट आदि;
>
> 22.1 एससी/एसटी, शारीरिक रूप से विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और ऐसे अन्य विशेष श्रेणी के अधिकारियों के लिए स्केल के मामले में छूट/रियायत/आरक्षण आदि के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश/निर्देश/प्रशासनिक निर्देश। अधिकारी ग्रेड के भीतर स्केल पदोन्नति को नीति का एक हिस्सा माना जाएगा और तदनुसार प्रभावी किया जाएगा।"

6. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि इनमें से प्रत्येक अपीलकर्ता बैंक द्वारा समान पदोन्नति नीति बनाई गई है

7. उपरोक्त पदोन्नति नीति के अनुसार, एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई आरक्षण नीति को शामिल करते हुए, बैंक एससी के लिए 15% आरक्षण और एसटी उम्मीदवारों के लिए 7.5% आरक्षण कर रहे हैं। यह भर्ती के प्रारंभिक स्तर पर और लिपिक संवर्ग में पदोन्नति के लिए भी किया जाता है। ऐसा आरक्षण लिपिक ग्रेड से अधिकारी ग्रेड में सबसे निचले रैंक तक पदोन्नति के लिए भी प्रदान किया जाता है, जिसे आमतौर पर जूनियर के रूप में जाना जाता है मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I (स्केल-I). हालाँकि, जब स्केल- I से अगले स्केल में पदोन्नति की बात आती है, जिसे मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल- II (स्केल- II) के रूप में जाना जाता है, तो बैंक इन पदोन्नतियों को करते समय कोई आरक्षण नहीं कर रहे हैं। बैंकों के अनुसार, यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 38012/6/83-पूर्व (एससीटी) दिनांक 01-11-1990 के कारण है। भारत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि समूह 'ए' पदों के भीतर कोई आरक्षण नहीं है।

8. पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ१ मामले में विचार किया था, जो 15-11-1992 को दिया गया निर्णय था। न्यायालय ने विशेष रूप से माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण प्रारंभिक नियुक्ति तक ही सीमित है और पदोन्नति के मामलों में आरक्षण तक इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त आदेश के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, 17-06-1995 से संविधान (सत्तरवें संशोधन) अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 में एक संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत, खंड 4 के बाद,

अनुच्छेद 16 में खंड 4 ए डाला गया था। संविधान का, जो निम्नलिखित भाषा में लिखा गया था:

> "4ए. इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जो राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।"

अनुच्छेद 16 का खंड (4) इस प्रकार लिखा गया है:

> "4. इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जिसका राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।"

खंड 4ए के सम्मिलन पर संवैधानिक स्थिति यह है कि राज्य को अब एससी और एसटी के पक्ष में पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार है, जहां राज्य की राय है कि एससी और एसटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य के अधीन सेवा. फिर भी, यह केवल एक सक्षम प्रावधान है जो राज्य को पदोन्नति के मामले में एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने का अधिकार देता है।

9. तथ्यों के ऐतिहासिक वर्णन को पूरा करने के लिए, यह उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि उपरोक्त संशोधन के बाद, यह प्रश्न उठा था कि क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति, जिसे आरक्षण के कारण त्वरित पदोन्नति मिलती है, को परिणामी वरिष्ठता भी मिलेगी उच्च पद पर यदि उसे सामान्य श्रेणी में अपने वरिष्ठ से पहले पदोन्नति मिल जाती है। न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर

भारत संघ और अन्य बनाम वीरपाल सिंह चौहान और अन्य२ के मामले में यह कहते हुए दिया कि पदोन्नति पर एससी/एसटी वर्ग के ऐसे कर्मचारी को परिणामी वरिष्ठता नहीं मिलेगी और उसकी वरिष्ठता पैनल की स्थिति से नियंत्रित होगी। इसके कारण एक और संविधान संशोधन हुआ और संसद ने संविधान (पचासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 बनाया, जिसके तहत अनुच्छेद 16 के खंड 4ए में संशोधन किया गया। संशोधित खंड 4ए इस प्रकार है:

> "4ए. इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों के वर्गों में परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। राज्य की राय का राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।"

10. उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर, संवैधानिक स्थिति यह है कि ऐसे एससी/एसटी उम्मीदवार जिन्हें त्वरित पदोन्नति का लाभ मिलता है, उन्हें परिणामी वरिष्ठता भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार, यह संशोधन वीरपाल सिंह चौहान (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के प्रभाव को रद्द कर देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि यह संशोधन 17.06.1995 से पूर्वव्यापी रूप से किया गया था, यानी अनुच्छेद 16 के मूल खंड 4 ए के लागू होने की तारीख से।

11. अनुच्छेद 16 के खंड 4ए के साथ-साथ खंड 48 की संवैधानिक वैधता, जिसे 85वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित किया गया था, को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य३ के मामले में इस चुनौती को खारिज कर दिया गया था। . न्यायालय ने विशेष रूप से माना कि ये प्रावधान अनुच्छेद 16(4) से आते हैं और इसलिए अनुच्छेद 16(4) की संरचना में परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके अलावा, वे ऐसा नहीं करते

किसी भी संवैधानिक आवश्यकता को समाप्त करना, अर्थात् 50% की अधिकतम सीमा (मात्रात्मक सीमा), क्रीमी लेयर की अवधारणा (गुणात्मक बहिष्करण), एक ओर ओबीसी और दूसरी ओर एससी/एसटी के बीच उप-वर्गीकरण। जैसा कि इंद्रा साहनी (सुप्रा) में आयोजित किया गया था। साथ ही, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि 50% की अधिकतम सीमा, क्रीमी लेयर की अवधारणा और बाध्यकारी कारण, अर्थात् पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता संवैधानिक आवश्यकताएं हैं जिनके बिना समानता की संरचना अनुच्छेद 16 में अवसर का पतन हो जाएगा।

12. संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन के बाद - खंड 4ए को शामिल करते हुए, भारत सरकार ने इस कार्यालय ज्ञापन की व्याख्या के रूप में दिनांक 13.08-1997 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया। विवाद की जड़ है. चूँकि इन अपीलों का परिणाम काफी हद तक इस ज्ञापन की व्याख्या पर निर्भर करता है, हम दिनांक 13-08-1997 के उक्त ओ.एम. को पूर्ण रूप से पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:

"नंबर 36012/18/95- ईस्ट (आरईएस) पीटी ii

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 13 अगस्त, 1997

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 19.8.1993 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में,

पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 16.11.1992 से पांच साल की अवधि तक जारी रखने की अनुमति दी थी।

2. इंदिरा साहनी के मामले में फैसले के परिणामस्वरूप संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16(4ए) को संविधान में शामिल किया गया। यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिनका राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

3. अनुच्छेद 16(4ए) के अनुसरण में, केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण 15.11.1997 से आगे उस समय तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक संवर्ग में उपरोक्त दो श्रेणियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पहुँच जाता है, जिसके बाद, पदोन्नति में आरक्षण संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक प्रतिनिधित्व बनाए रखना जारी रहेगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों को तत्काल अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वैधानिक निकायों आदि के ध्यान में लाएँ।

एसडी/-

(वाई.जी. परांडे)

निदेशक (आरक्षण)"

13. एससी और एसटी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिवादी संघों ने मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि

अधिकारियों की एक श्रेणी से उच्च श्रेणी के अधिकारियों तक पदोन्नति के लिए भी आरक्षण की स्पष्ट नीति होने के बावजूद, अपीलकर्ता बैंकों ने पदोन्नति करते समय इस तरह के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों की पदोन्नति नीति के अनुसार एससी/एसटी अधिकारियों के लिए इस तरह के आरक्षण को निर्दिष्ट करने के लिए बैंक के खिलाफ निर्देश देने की मांग करते हुए परमादेश मांगा गया था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 16(4ए) केवल एक सक्षम प्रावधान था जो राज्य को पदोन्नति के संबंध में आरक्षण के प्रावधान करने की अनुमति देता है। हालाँकि, मौजूदा मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई जो पदोन्नति के लिए ऐसे किसी विशिष्ट प्रावधान को प्रदर्शित कर सके।

14. रिट याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी। डिविजन बेंच ने विपरीत रुख अपनाया है। डिविजन बेंच के फैसले को पढ़ने से पता चलेगा कि यह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के पीछे की भावना से चला गया है जो सकारात्मक कार्यों की प्रकृति में हैं जिन्हें राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से आरक्षण प्रदान करने में लिया जा सकता है। पिछड़े लोग और इसमें एससी और एसटी वर्ग शामिल हैं। इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 16(4) विशेष रूप से उन लोगों को राज्य की सत्ता में उचित हिस्सा देने के लिए बनाया गया है जो मुख्य रूप से अपने सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इससे बाहर हैं क्योंकि आरक्षण नागरिकों के ऐसे वर्गों को स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। राष्ट्र की सेवा करने का अवसर और इस प्रकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुरक्षा, स्थिति, तुलनात्मक समृद्धि और प्रभाव प्राप्त करना। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण प्रदान करने के लिए एक सक्षम प्रावधान पेश करते हुए खंड 4ए को शामिल किया गया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने यूको बैंक के

साथ-साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में विभिन्न ग्रेड/स्केल/कैडर में एससी/एसटी अधिकारियों की ताकत दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर रखे गए आंकड़ों पर ध्यान दिया और पाया कि शायद ही कोई प्रतिनिधित्व था। उच्च वेतनमान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की तो बात ही क्या करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में दिए गए आंकड़े आक्षेपित निर्णय के पैरा 22 में नोट किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

> "22.....एमएमजी:III-IV:, एसएमजी :IV-V; एसएमजी VVI; टीएमजी VI- टीएमजी VII में वर्ष 1997 से 2008 तक की पदोन्नति के लिए एक समेकित विवरण इस संबंध में एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करेगा। पूरे पहलू को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्योंकि एससी/एसटी के लिए कम से कम या कोई प्रस्तुति नहीं दी गई है। 20 पदों की कुल पदोन्नति के लिए इन गणनाओं के अनुसार, वर्ष 2007 में केवल एक एससी उम्मीदवार को पदोन्नति मिली और 171 की कुल पदोन्नति के लिए, इन श्रेणियों के भीतर केवल नौ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पदोन्नति मिली। वर्ष 1997 और 2002 में क्रमशः 19 पदों और छह पदों के लिए की गई पदोन्नति में किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को पदोन्नति नहीं दी गई। वर्ष 1999 में, कुल 126 पदों के लिए केवल एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को पदोन्नति दी गई। इसी तरह, वर्ष 2006 में कुल 308 पदोन्नतियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के केवल 36 अभ्यर्थियों को पदोन्नत किया गया था।"

न्यायालय ने निम्नलिखित विवरण देते हुए यूकोबैंक में भी लगभग समान सुविधा देखी:

"23. ... यूको बैंक में 31.3.2008 को एससी/एसटी अधिकारियों के पैमाने के अनुसार प्रतिनिधित्व के अनुसार, स्केल IV पदों में 50 एससी अधिकारियों और स्केल V पदों में 31 एसटी अधिकारियों की कमी है। 10 एससी अधिकारियों और 7 एसटी अधिकारियों की कमी है; स्केल VI में, 5 एससी अधिकारियों और 2 एसटी अधिकारियों की कमी है और स्केल VII पदों में, 3 एससी अधिकारियों और एक एसटी अधिकारी की कमी है।"

15. कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13-08-1997 को उपरोक्त संवैधानिक भावना के साथ-साथ बैंकों में एससी/एसटी श्रेणी के अधिकारियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आलोक में पढ़ा गया है, यह मानते हुए कि उक्त ओ.एम. का अधिदेश है। आरक्षण प्रदान करना था

16. ऐसा मानते हुए, उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 335 पर आधारित बैंकों के उस तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसके आधार पर यह तर्क दिया गया था कि पदोन्नति में आरक्षण के नियम की शुरूआत से बैंकों के प्रशासन की दक्षता कम हो जाएगी। न्यायालय ने विशेष रूप से संविधान के बयासीवें संशोधन पर ध्यान दिया, जिसे 08-09-2000 से प्रभावी बनाया गया था और यह प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद में कुछ भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में योग्यता में छूट के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोका जाएगा। संघ या राज्य के मामलों के संबंध में किसी भी वर्ग या वर्गों की सेवाओं या पदों पर पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी भी परीक्षा में अंक प्राप्त करना या मूल्यांकन के मानकों को कम करना। उच्च न्यायालय की राय में, जब संविधान ने वंचित समुदायों को ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा दी है ताकि वे संविधान द्वारा गारंटीकृत समान अवसरों का आनंद उठा सकें, तो

बिना किसी ठोस कारण के एक दशक तक पदोन्नति में आरक्षण देने के मामले पर बैंकों का सोए रहना उचित नहीं है।

17. हमारे सामने भी दोनों पक्षों का रुख वही है. बैंकों के अनुसार, दिनांक 13-08-1997 के ओ.एम. के माध्यम से "सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वर्तमान की तरह पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने का निर्णय लिया गया है..." इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि यह ओ.एम. पदोन्नति के मामले में कोई आरक्षण नहीं दिया लेकिन जो पहले से मौजूद था उसे जारी रखा गया है। मेसर्स सी.एस. वैद्यनाथन और राजू रामचंद्रन, विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्होंने इन बैंकों के लिए बहस की, ओ.एम. में प्रयुक्त उपरोक्त भाषा पर जोर दिया। और प्रस्तुत किया कि केवल मौजूदा स्थिति जारी रही और जो स्थिति मौजूदा थी वह यह थी कि आरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। एकमात्र प्रावधान जो अस्तित्व में था, वह शिथिल मानकों को लागू करने के लिए 5,700/- के मूल वेतन से अधिक पाने वाली क्लास ए (क्लास I) सेवा में पदोन्नति के लिए एससी/एसटी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी का निर्णय करना था। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसा प्रावधान ओ.एम. में मौजूद था। दिनांक 01-11-1990. यह बताया गया कि इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में। इन श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों को दी जाने वाली रियायत के बारे में उल्लेख किया गया था और पैरा 3 में यह स्पष्ट किया गया था कि ओ.एम. के पैरा 2 और 3 में चयन द्वारा पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है। दिनांक 01-11-1990 इस प्रकार पढ़ें:

> "2. हालांकि ऊपर उद्धृत ओएम में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि श्रेणी I (अब ग्रुप ए) के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में उन पदों पर, जिनका अंतिम वेतन 2000/- रुपये प्रति माह या उससे कम है (अब संशोधित होकर 5700 रुपये हो गया है) -अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिया जाएगा रियायत अर्थात् "वे

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले क्षेत्र में इतने वरिष्ठ हैं कि रिक्तियों की संख्या के भीतर हैं जिसके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, उन्हें उस सूची में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि उन पर विचार न किया जाए पदोन्नति के लिए अयोग्य", कुछ तिमाहियों में संदेह व्यक्त किया गया है कि क्या ऊपर दी गई रियायत आरक्षण है या रियायत।

3. इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि समूह पदों के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में, जिसका अंतिम वेतन रु. 5700/ प्रतिमाह कोई आरक्षण नहीं है।"

18. यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त दो परिपत्रों अर्थात् ओ.एम. का एक संयुक्त वाचन। दिनांक 01-11-1990 और 13-08-1997 से यह स्पष्ट होगा कि पदोन्नति के मामले में प्रावधान रियायत के लिए किया गया था न कि आरक्षण के लिए। इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया गया जहां रियायत और आरक्षण के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझाया गया है:

(i) नेशनल फेडरेशन ऑफ एस.बी.आई. और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

"15. 1987 में, भारत सरकार ने उक्त ब्रोशर का 7 वां संस्करण जारी किया, जिसमें पैरा 9.2, ऊपर उद्धृत के अनुरूप, इस प्रकार है:

एमएचए ओएम नंबर 1/9/69. स्था.(एससीटी) दिनांक 26-3-70 और कार्मिक एवं एआर विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/10/74-स्था. (एससीटी) दिनांक 23-12-1974"

"9.2 चयन विधि द्वारा पदोन्नति।- (ए) समूह ए (श्रेणी- ।) के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति। समूह ए (श्रेणी ।) के भीतर पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति में, जिसमें प्रति माह 2000 रुपये या उससे कम का अंतिम वेतन होता है, (संशोधित वेतनमान में 2250 रुपये प्रति माह या उससे कम) कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, जो पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में पर्याप्त वरिष्ठ हैं ताकि रिक्तियों की संख्या के भीतर चयन किया जा सके। सूची तैयार कर ली गई है, उन्हें उस सूची में शामिल किया जाएगा, बशर्ते उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य न माना जाए। हालाँकि, चयन सूची में उनकी स्थिति वही होगी जो उन्हें उनके रिकॉर्ड के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सौंपी गई थी। सेवा। इस प्रयोजन के लिए उन्हें उनकी सेवा के रिकॉर्ड के आधार पर अन्यथा दी जाने वाली ग्रेडिंग से एक ग्रेड अधिक नहीं दी जाएगी।

समूह ए (कक्षा ।) में उच्च श्रेणी के पदों पर चयन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संभावनाओं में सुधार करने के लिए।

(i) ग्रुप ए (श्रेणी ।) सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण और सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन में भाग लेने के लिए अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद आदि में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का भी लाभ उठाया जाएगा।

(ii) कक्षा I में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों की यह विशेष जिम्मेदारी होगी कि वे अपने काम की गुणवत्ता में सुधार के लिए सलाह और मार्गदर्शन दें।

Xxx xxx xxx

19. हम विद्वान वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं। यह सभी हाथों से स्वीकार किया गया है कि जहां तक वर्ग I के भीतर पदोन्नति का संबंध है - जिसके साथ अकेले 26-3-1970 का ज्ञापन संबंधित है - आरक्षण के नियम को लागू करने के लिए भारत सरकार के कोई आदेश नहीं हैं। हमने यहां पहले 11-7-1968 के पहले के ज्ञापन का उल्लेख किया है (जो बदले में 8-11-1963 के एक और भी पहले के ज्ञापन को संदर्भित करता है)। पहले के ज्ञापनों में कक्षा II, III और IV में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन कक्षा I में पदोन्नति के लिए नहीं और किसी भी दर पर कक्षा I के भीतर पदोन्नति के लिए नहीं। न ही दिनांक 26-3-1970 का ज्ञापन ऐसे आरक्षण का प्रावधान करता है। विचार स्वतः स्पष्ट है. जबकि आरक्षण का नियम निचली श्रेणियों, जैसे कि कक्षा II, III और IV (उक्त ज्ञापनों में निर्दिष्ट सीमा तक) पर लागू किया गया है, कक्षा I के भीतर पदोन्नति के मामले में ऐसा कोई आरक्षण उचित नहीं समझा गया। आरक्षण के बजाय, एक रियायत प्रदान की गई थी, रियायत यहाँ ऊपर बताई गई है।

यही वह तथ्य है जिसे वित्त मंत्रालय के बाद के पत्रों में दोहराया, पुष्ट और स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 30-5-1981 और उसके बाद के पत्र दिनांक 26-31970 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन या परिवर्तन नहीं करते हैं बल्कि केवल इसकी व्याख्या करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि इसमें क्या निहित है। 7 वें संस्करण में पैरा 9.2 का प्रतिपादन भी ऐसा ही है। ब्रोशर में. वे बस इतना कहते हैं कि आरक्षण का नियम कक्षा I के भीतर पदोन्नति पर लागू नहीं होता है (यानी, संशोधित वेतनमान में 2250 रुपये प्रति माह या उससे कम अंतिम वेतन वाले

पदों पर चयन के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति) लेकिन रियायत मिलती है दिनांक 26-3-1970 के ज्ञापन के पैरा 2 के संदर्भ में इस संबंध में प्रावधान किया गया है, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि या तो वित्त मंत्रालय के पत्र या ब्रोशर के 7 वें संस्करण में पैरा 9.2 का प्रतिपादन असंगत है दिनांक 26-3-1970 के ज्ञापन के साथ या कि वे सरकार के आदेशों के विपरीत हैं।

> 31. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि कक्षा । के भीतर पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में, जिसमें प्रति माह संशोधित वेतनमान में 2250 रुपये या उससे कम का अंतिम वेतन होता है, अनुसूचित जाति के पक्ष में कोई आरक्षण नहीं है। /अनुसूचित जनजातियाँ लेकिन वे गृह मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26-3-1970 के पैरा 2 में निहित रियायत के हकदार हैं। रियायत यह है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारी जो पदोन्नति के लिए विचाराधीन क्षेत्र में इतने वरिष्ठ हों कि रिक्तियों की संख्या के भीतर हों, जिसके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, उन्हें चयन सूची में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। (इस नियम को निर्णय के मुख्य भाग में एक देकर समझाया गया है उदाहरण, जिसे यहां दोहराना आवश्यक नहीं है।) हालांकि, चयन सूची में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों की स्थिति वही होगी जो उन्हें उनकी सेवा के रिकॉर्ड के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सौंपी गई है। उक्त उम्मीदवार, उक्त चयन के प्रयोजन के लिए, उनकी सेवा के रिकॉर्ड के आधार पर अन्यथा उन्हें दी जाने वाली ग्रेडिंग से एक ग्रेड अधिक के हकदार नहीं होंगे। यह ब्रोशर के पैरा 9 का भी तात्पर्य है क्योंकि यह कक्षा । के भीतर पदोन्नति से संबंधित है।"

(ii) प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक (अब असम ग्रामीण विकास बैंक के रूप में जाना जाता है)

"24. संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम श्री मेहता से सहमत हैं कि दिनांक 10-6-1997 के परिपत्र में शामिल आरक्षण पदों से संबंधित प्रावधानों की गलत व्याख्या की गई है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त शर्त एक रियायत की प्रकृति में है जैसा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को स्वचालित रूप से नियुक्त होने का अवसर देने के लिए नाबार्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 9-11-1994 में विचार किया गया था। , यदि वह उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के भीतर आता है। ऐसे उम्मीदवार को चयन की प्रक्रिया से बचने में सक्षम बनाने के लिए यह एक रियायत थी, जिसे अन्य सभी उम्मीदवारों से गुजरना आवश्यक था।

25. उक्त प्रावधान को नेशनल फेडरेशन ऑफ एसबीआई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1995) 3 एससीसी 532 मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ द्वारा बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है, जैसा कि उक्त निर्णय में बताया गया है, विचार का क्षेत्र सूची है उपलब्ध रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से वरिष्ठता के आधार पर चुने गए चयनित उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा और केवल विचार के क्षेत्र में आने से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार स्वत: चयन का हकदार नहीं होगा। आरक्षण से संबंधित रियायत का मतलब यह नहीं है कि किसी भी रिक्त पद को ऐसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए

आरक्षित रखा जाना आवश्यक था। ऐसा केवल तभी होता है जब ऐसा उम्मीदवार रिक्तियों की संख्या के भीतर आता है कि चयन प्रक्रियाओं से गुज़रे बिना नियुक्ति के लिए उसे ऐसी रियायत लागू होगी।"

19. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, जिनमें डॉ. कृष्ण सिंह चौहान, श्री ई.सी. विद्या सागर, श्री ए.जी. सुब्बा राव, श्री सत्यजीत ए. देसाई और श्री सी.के. शामिल हैं। चन्द्रशेखर एडवोकेट्स ने अपने फैसले के समर्थन में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर मजबूत भरोसा जताया, जिसमें अधिकारियों की श्रेणी, विशेष रूप से स्केल IV और उससे ऊपर के एससी/एसटी कर्मचारियों का लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं होने की निराशाजनक स्थिति का अनुमान लगाया गया था।

20. इन उत्तरदाताओं द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि 14-01-2010 और 01-02-2010 को इन उत्तरदाताओं की रिट अपील की अनुमति देने वाली डिवीजन बेंच के फैसले के बाद, केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया था। . इसके बाद बैंक ने एसएलपी दायर की है। उनका वर्तमान रुख कि कोई आरक्षण नहीं होगा, बल्कि उन अधिकारियों पर विचार करके केवल रियायत दी जाएगी जो क्षेत्र के भीतर रहने के लिए पर्याप्त वरिष्ठ हैं और अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं, भ्रामक है। दरअसल, पिछली सरकार द्वारा सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए संसद के दोनों सदनों में एक विधेयक पारित किया गया था, (यानी 117 वां संवैधानिक संशोधन), जो बाद में समाप्त हो गया था। तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार अब कोई अलग रुख नहीं अपना सकती.

21 बैंकों का यह दावा कि स्केल-I स्तर से आगे पदोन्नति में आरक्षण देने से दक्षता प्रभावित होगी, का भी यह तर्क देकर खंडन किया गया कि एससी/एसटी से संबंधित अधिकारियों को केवल उनकी योग्यता/प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत कार्य नहीं

कर सकता। यह प्रस्तुत किया गया था कि नेशनल फेडरेशन ऑफ एस.बी.(सुप्रा) में दिनांक 10-03-1995 का निर्णय और 77 वें संशोधन से पहले बैंकों द्वारा भरोसा किया गया था जो 17-06-1995 को पारित हुआ। उनके अनुसार, एम. नागराज (सुप्रा) का निर्णय बैंकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देता है। 117 वें संशोधन विधेयक का स्पष्ट संदर्भ दिया गया था, जिस पर हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति कर्मचारी महासंघ और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश समान वर्गकर्मचारी कल्याण महासंघ और अन्य६ में न्यायिक नोटिस लिया गया था6 उक्त निर्णय के पैरा 32 से 34 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था, जो इस प्रकार हैं :

> "32. यहां, हम एक वकील से अपेक्षित आचरण के बारे में रोंडेल बनाम वॉर्स्ली (1967) 1 क्यूबी 443 में लॉर्ड डेनिंग के शब्दों की ओर इशारा करना चाहेंगे:
>
> "... एक वकील के रूप में वह न्यायाधीश के साथ समान रूप से न्याय मंत्री हैं... मैं कहता हूं 'सम्मानपूर्वक वह सब कुछ कर सकते हैं' क्योंकि उनका कर्तव्य केवल अपने मुवक्किल के प्रति नहीं है। उनका न्यायालय के प्रति भी कर्तव्य है जो सर्वोपरि है। यह मान लेना ग़लत है कि वह अपने ग्राहक का मुखपत्र है जो वह कहना चाहता है या जो वह निर्देशित करता है उसे करने का उसका उपकरण है। वह इनमें से कुछ भी नहीं है। वह एक उच्च उद्देश्य के प्रति निष्ठा रखता है। यह सत्य का कारण है और न्याय। उसे जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। उसे जानबूझकर सच्चाई को छिपाना नहीं चाहिए। उसे धोखाधड़ी का आरोप अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं लगाना चाहिए, यानी इसके समर्थन में सबूत के बिना। उसे सभी संबंधित अधिकारियों को पेश करना होगा, यहां तक कि वे भी जो

उसके खिलाफ हैं उसे यह अवश्य देखना चाहिए कि उसका मुवक्किल, यदि आदेश दिया गया है, प्रासंगिक दस्तावेजों का खुलासा करता है, यहां तक कि वे भी जो उसके मामले के लिए घातक हैं। उसे अपने मुवक्किल के सबसे विशिष्ट निर्देशों की अवहेलना करनी चाहिए, यदि वे अदालत के प्रति उसके कर्तव्य के साथ टकराव करते हैं। जिस कोड की आवश्यकता होती है बैरिस्टर के लिए यह सब करना कोई कानून की संहिता नहीं है। यह सम्मान की संहिता है।" (क्यूबीपी. 502)

(जोर दिया गया)

हमारी राय में, लॉर्ड डेनिंग का उपरोक्त उपदेश कानूनी पेशे के सदस्यों द्वारा बनाए रखने के लिए अपेक्षित नैतिक, नैतिक और पेशेवर आचरण के बहुत उच्च मानक का एक उपयुक्त प्रदर्शन है। हम इस देश में किसी वकील/वकील से कम की उम्मीद नहीं करते हैं।

33. इधर, इस मामले में 26-4-2010 को हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से एक बयान दिया गया था. कि "राज्य का इरादा एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व के संबंध में अधिक विवरण एकत्र करने और उचित समय के भीतर यानी आवश्यक विवरण और डेटा एकत्र करने के लगभग तीन महीने के भीतर उचित आदेश पारित करने का है"। 2009 की एसएलपी (सी) संख्या 30143 में योग्यता के आधार पर निर्णय को बहुत चतुराई से टालने के बाद, राज्य इस न्यायालय में दिए गए गंभीर बयान पर खरा उतरने में पूरी तरह से विफल रहा है। यह 26-4-2010 से आज तक हैशेड और हेम्ड और प्रीवेरिकेटेड है। अपेक्षित डेटा उपलब्ध होने के बावजूद, राज्य द्वारा पहले से अपनाई गई आरक्षण की नीति लागू नहीं की गई है। इसलिए, हम डॉ. धवन

से सहमत नहीं हैं कि आवेदक आरक्षण में नीति अपनाने के लिए परमादेश की मांग कर रहे हैं। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि आवेदक चाहते हैं कि राज्य अपने निर्णय स्वयं लागू करे। प्रार्थना है: "प्रतिवादी/राज्य सरकार को एक महीने की अवधि के भीतर 25-4-2011 को पहले से उपलब्ध/कैबिनेट उपसमिति को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर समयबद्ध तरीके से मामले का निर्णय लेने का निर्देश दें और निर्णय लंबित होने तक सभी पदोन्नतियों पर रोक लगाने का निर्देश दें। इस मामले में लिया गया।"

34. उपरोक्त राहत न देने के लिए राज्य द्वारा पेश किया गया अंतिम बहाना यह है कि राज्य अब 117 वें संविधान संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा कर रहा है। हम 26-4-2010 को इस न्यायालय में दिए गए बयान का सम्मान न करने के लिए दिए गए कारणों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह न्यायालय समय विस्तार के लिए राज्य द्वारा किए गए अनुरोधों पर बहुत अधिक विचारशील रहा है। ये आखिरी बहाना प्रस्तावित सत्रहवें संवैधानिक संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा करना ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका है। जैसा कि पहले कहा गया है, प्रस्तावित 117 वां संवैधानिक संशोधन परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति देने के लिए याचिकाकर्ता के परिवार की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन द्वारा, मौजूदा अनुच्छेद 16 खंड (4-ए) को निम्नलिखित खंड (4-ए) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।

"16. (4-ए) संविधान में कहीं और कुछ भी निहित होने के बावजूद, क्रमशः अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पिछड़ा माना जाएगा और इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 335 में कुछ भी नहीं रोका जाएगा। राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से रोक दिया जाएगा। राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ।"

22. रोहतास भांखर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर भी बहुत अधिक भरोसा किया गया था, जिसके आधार पर यह तर्क दिया गया था कि उस मामले में बैंकों की निर्भरता ओ.एम. पर थी। दिनांक 22.07.1997 पूरी तरह से ग़लत था, क्योंकि इस मामले में उक्त ओ.एम. निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई चर्चा के अनुसार इसे कानून की दृष्टि से बुरा माना जाता है:

"9. हम यूटी, चंडीगढ़ बनाम कुलदीप सिंह, (1997) 9 एससीसी 199 के फैसले से सम्मानजनक सहमत हैं और इसे मंजूरी देते हैं। आमतौर पर, हम मामलों के निपटारे के लिए मामले को नियमित बेंच के पास भेज देते, लेकिन ध्यान रखते हुए विवाद की प्रकृति और तथ्य यह है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दिल्ली (संक्षेप में "द ट्रिब्यूनल") ने एस विनोद कुमार बनाम भारत संघ (1996) 6 एसईसी 580 का पालन किया है जो अच्छा कानून नहीं है और परिणामस्वरूप 1997 ओएम है यह भी अवैध है, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं की

पीड़ा को लंबे समय तक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे राहत के हकदार हैं।

10. परिणामस्वरूप, सिविल अपील की अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। 1997 के ओएम को अवैध घोषित कर दिया गया है. उत्तरदाताओं को अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड बी/ग्रेड ।) लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 1996 में आरक्षण प्रदान करके परिणामों को संशोधित करने और अपीलकर्ताओं को सभी परिणामी राहतें देने का निर्देश दिया जाता है, यदि अब तक नहीं दी गई है। कोई लागत नहीं।"

23. इसमें शामिल मुख्य मुद्दे पर चर्चा करने से पहले, मुख्य मुद्दे से जुड़ी कुछ कमियों को दूर करना चीजों की उपयुक्तता में होगा। वास्तव में, यह अभ्यास उस मुद्दे के सटीक सार को समझने में सुविधा प्रदान करेगा जिसे संबोधित करने और उत्तर देने की आवश्यकता है।

24. सबसे पहले, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अनुच्छेद 15 और 16 में परिकल्पित संवैधानिक स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं है, जहां तक ये प्रावधान राज्य को एससी/एसटी वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण बनाकर उनके पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं। संघ या राज्य में रोजगार में (या उस मामले के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र/प्राधिकरण जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में माना जाता है)। ऐसे एससी/एसटी कर्मचारियों के आरक्षण से संबंधित मुद्दों से संबंधित कोई भी अभ्यास करते समय इन प्रावधानों में अंतर्निहित प्रशंसनीय उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसके अलावा, ऐसा आरक्षण न केवल प्रवेश स्तर पर किया जा सकता है, बल्कि इसकी अनुमति भी है। पदोन्नति के मामले भी। साथ ही,

यह भी ध्यान में रखना होगा कि संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4 और 4 ए केवल सक्षम प्रावधान हैं जो राज्य को इन श्रेणी के व्यक्तियों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। जहां तक किसी वर्ग या वर्ग के पद पर पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के प्रावधान करने का सवाल है, ऐसा प्रावधान एससी/एसटी श्रेणी के कर्मचारियों के पक्ष में किया जा सकता है, यदि राज्य की राय में उन्हें राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रावधान बनाने की शक्ति राज्य के पास है, लेकिन साथ ही, अदालतें आवश्यक रूप से ऐसा प्रावधान करने के लिए राज्य को कोई परमादेश जारी नहीं कर सकती हैं। किसी भी स्थिति में कार्य करना राज्य का काम है, और ऐसी सकारात्मक कार्यवाही करने के लिए. बेशक, जब भी भर्ती या पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए ऐसा कोई प्रावधान मौजूद है, तो यह एससी/एसटी वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में एक प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान करेगा और पदों को आरक्षित करने में किसी भी प्राधिकारी की ओर से विफलता पर, चयन करते समय/पदोन्नति, इन प्रावधानों के लाभार्थी अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जिस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए वह यह है कि चयन या पदोन्नति के मामले में आरक्षण के प्रावधान का अस्तित्व, जैसा भी मामला हो, परमादेश मांगने के लिए अनिवार्य शर्त है क्योंकि यह केवल तभी होता है जब राज्य द्वारा ऐसा प्रावधान किया जाता है, यह एक अधिकार है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पक्ष में अर्जित होगा, अन्यथा नहीं।

25. इसमें कोई विवाद नहीं है कि लिपिक ग्रेड से अधिकारी ग्रेड में सबसे निचले रैंक तक पदोन्नति के लिए आरक्षण के नियम का पालन किया जाता है। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या आरक्षण का कोई प्रावधान है जब अधिकारी ग्रेड में एक विशेष रैंक से उक्त ग्रेड में अगले रैंक, अर्थात् स्केल- । से स्केल- ॥, स्केल तक पदोन्नति की जानी हो। -॥ से स्केल-॥। और इसी तरह।

26. इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि केंद्र सरकार की आरक्षण नीति अपीलकर्ता बैंकों पर लागू होती है। यह दोनों पक्षों का सामान्य मामला है. वास्तव में, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता बैंकों द्वारा बनाई गई पदोन्नति नीतियों में इस आशय का एक विशिष्ट प्रावधान है।

27. अगली बात जो ध्यान में रखनी है वह दो कार्यालय ज्ञापन हैं, एक दिनांक 1.11.1990 और दूसरा दिनांक 13.8.1997, जिन्हें पार्टियों के वकील द्वारा संदर्भित किया गया है। हमने पहले ही उपरोक्त दो कार्यालय ज्ञापन पुनः प्रस्तुत कर दिए हैं . जहां तक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1.11.1990 का संबंध है, इस प्रावधान को मात्र पढ़ने से निम्नलिखित दो पहलू प्रतिबिंबित होंगे:

(ए) क्लास- । (ग्रुप-ए) पद के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में एससी/एसटी उम्मीदवारों को 'रियायत' दी जानी है।

(बी) यह रियायत उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले क्षेत्र में इतने वरिष्ठ हैं कि रिक्तियों की संख्या के भीतर हों जिसके लिए चयन सूची तैयार की जानी है।

इस प्रकार, पहली आवश्यकता यह है कि ऐसे एससी/एसटी उम्मीदवार जो पदोन्नति के लिए विचाराधीन क्षेत्र में आते हैं, रिक्तियों की संख्या के भीतर पर्याप्त वरिष्ठ हों। एक बार जब वे उपरोक्त विचार क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उन्हें सूची में शामिल करना होगा, बशर्ते कि उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं माना जाए। उपरोक्त से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक बार जब वे पदोन्नति के लिए विचाराधीन क्षेत्र में आ जाते हैं ताकि रिक्तियों की संख्या के भीतर आ सकें जिसके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, तो ऐसे एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए उन्हें पदोन्नति से वंचित करना एकमात्र प्रतिबंध है। ऐसा तब होता है जब उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य पाया जाता है। सामान्य श्रेणी के अन्य अधिकारियों के लिए, पदोन्नति के नियम के आधार पर,

तुलनात्मक योग्यता या योग्यता के आधार पर चयन आदि के आधार पर बहुत सख्त मानदंड हो सकते हैं। हालांकि, ऐसे वरिष्ठ के मामले में एससी/ एसटी उम्मीदवारों के लिए मानदंड वरिष्ठता, फिटनेस के अधीन प्रतीत होता है।

(सी) यह ओएम विशेष रूप से इस संदेह को दूर करता है कि उपरोक्त प्रावधान केवल एक रियायत है और एससी/एसटी उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षण नहीं है, क्योंकि ओएम के पैरा 3 में कहा गया है कि "इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रुप-ए पद के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में, जिसमें प्रति माह 5,7001 रुपये का अंतिम वेतन होता है, कोई आरक्षण नहीं है"। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जहां तक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1.11.1990 का संबंध है, 5,700 रुपये प्रति माह के अंतिम वेतन वाले समूह-ए पदों के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में एससी/एसटी उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था।

28. निःसंदेह, यह कार्यालय ज्ञापन वर्ष 1990 में जारी किया गया था, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन से बहुत पहले, जिसे वर्ष 1995 में खंड 4ए डालकर लागू किया गया था। हालाँकि, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, खंड 4ए एक सक्षम प्रावधान है जो राज्य को पदोन्नति के मामले में और साथ ही एससी/एसटी कर्मचारियों के पक्ष में आरक्षण देने का अधिकार देता है। ग्रुप-ए पद के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में 1.11.1990 तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसमें प्रति माह 5,700/- रुपये का अंतिम वेतन होता है।

29. इसे समझने के बाद, हम यह पता लगाने के लिए दिनांक 13.8.1997 के कार्यालय ज्ञापन पर आए हैं कि क्या यह ज्ञापन एससी/एसटी कर्मचारियों के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करता है, जबकि कोई अन्य कार्यालय ज्ञापन या परिपत्र नहीं है। इस प्रयोजन के लिए नियम आदि को रिकार्ड में प्रस्तुत किया जाता है।

30. हम पहले ही ऊपर नोट कर चुके हैं कि इंद्रा साहनी (सुप्रा) में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में कहा गया था कि अनुच्छेद 16 का खंड 4 पदोन्नति के मामलों को कवर नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि उक्त खंड के अनुसार किसी के पक्ष में कोई आरक्षण नहीं है। पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुमति है। उक्त निर्णय में इस आदेश के प्रभाव को खत्म करने के लिए 17-06-1995 से संविधान के सत्तरवें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4ए डाला गया था। हालाँकि, यह भी रिकॉर्ड की बात है कि इंद्रा साहनी के मामले (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि पदोन्नति में एससी/एसटी के लिए आरक्षण 16-11-1992 से पांच साल की अवधि तक जारी रहेगा। इसका मतलब यह था कि यदि पदोन्नति के मामले में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो उक्त मामले में इस आदेश के बावजूद कि ऐसा आरक्षण स्वीकार्य नहीं है, उन प्रावधानों को 16-11- 1992 से पांच साल की अवधि तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी। - उसके बाद पांच साल की समाप्ति से पहले पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण का प्रावधान करके खंड 4 ए के रूप में संवैधानिक प्रावधान शामिल किया गया था। इन तथ्यों को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13-08-1997 के पहले दो पैराग्राफ में नोट किया गया है। इसके बाद, उक्त ज्ञापन के तीसरे पैरा में, यह प्रदान किया गया है:

> "3. अनुच्छेद 16(4ए) के अनुसरण में, केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण 15.11.1997 से आगे उस समय तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। चूंकि प्रत्येक संवर्ग में उपरोक्त दो श्रेणियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच जाता है, जिसके बाद, पदोन्नति में आरक्षण संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक प्रतिनिधित्व बनाए रखना जारी रहेगा।"

31. एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, जो उस समय प्रचलित था, को जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिसे इंद्रा साहनी (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के अनुसार 15-11-1997 तक जारी रखा जाना था। 15-11-1997 से आगे भी जब तक कि प्रत्येक संवर्ग में उपरोक्त दो श्रेणियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता। इस प्रकार, इस पैरा को पढ़ने से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मौजूदा प्रावधान को 15-11-1997 से आगे जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, इस ज्ञापन में एससी/एसटी कर्मचारियों के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण के लिए कोई नया प्रावधान नहीं किया गया।

32. हमने पहले ही ऊपर देखा है कि ग्रुप-ए पदों के भीतर पदोन्नति के मामलों में, जिसमें प्रति माह 5,700/- रुपये का अंतिम वेतन होता है, किसी भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। इन दोनों कार्यालय ज्ञापनों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, पदोन्नति के मामले में इस तरह के आरक्षण का सबूत देने वाले किसी अन्य प्रावधान या नियम के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि समूह-ए पदों के भीतर रुपये के अंतिम वेतन तक पदोन्नति में आरक्षण था। 5,700/- प्रति माह. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में निहित उच्च आदर्शों के साथ-साथ इस तथ्य को भी खारिज कर दिया है कि इन बैंकों में समूह-IV और उससे ऊपर के एससी/एसटी वर्ग के अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा हो सकता है. यह केवल इस प्रकृति का प्रावधान करने का औचित्य प्रदान कर सकता है। हालाँकि, ऐसे प्रावधान के अभाव में, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13-08-1997 की भाषा को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं पढ़ा जा सकता है। यह राज्य का काम है कि वह जमीनी हकीकत का जायजा ले और यह निर्णय ले कि क्या उपरोक्त पद पर पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान करना आवश्यक है।

33. इतना कहने के बाद, एक अन्य पहलू जिस पर इस स्तर पर आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना है, वह हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इस पहलू, जिसे हम अभी इंगित करने जा रहे हैं, को विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने-अपने फैसले में कहा।

34. यह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01-11-1990 में प्रदान किया गया है, और हमने बार-बार ऊपर कहा है, कि केवल उन समूह ए पदों के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है, जिनका अंतिम वेतन 5,700/- रुपये प्रति माह है। मामलों में, यह केवल रियायत ही लागू होती है। हमने ऊपर दी गई चर्चा के अनुसार, इस संबंध में अपीलकर्ता बैंकों के तर्क को स्वीकार कर लिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पदोन्नति में आरक्षण उन पदों पर चयन द्वारा प्रदान किया जाता है जिनमें प्रति माह (पूर्व-संशोधित) 5,700/ रुपये से कम वेतन होता है।

35. सार्वजनिक उद्यम विभाग ने दिनांक 08-11-2004 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था जिसमें आरक्षण के प्रयोजनों के लिए रु. 5,700/- की वेतन सीमा का उल्लेख रु. 18,300/- (5 वें केंद्रीय वेतन आयोग) के रूप में किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में जो औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न का पालन कर रहे हैं, मौद्रिक सीमा रुपये तय की गई थी। 20,800/- (01-01-1996 से, यानी 5 वें केंद्रीय वेतन आयोग से)। अपीलकर्ता बैंकों में उक्त वेतन सीमा तभी प्राप्त होती है जब कोई अधिकारी स्केल-VII तक पहुँच जाता है। एक फोर्टियोरारी के रूप में, पदोन्नति के मामले में कोई आरक्षण नहीं की नीति केवल स्केल-VII और उससे ऊपर पर लागू होती है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से इस प्रकार है कि जहां तक स्केल-I से स्केल-II, स्केल-II से स्केल-III, स्केल-III से स्केल-IV, स्केल-IV से स्केल-V, स्केल F V से स्केल-VI तक पदोन्नति की बात है। संबंधित, आरक्षण प्रदान किया जाना है। इसलिए,

अपीलकर्ता बैंक उपरोक्त ज्ञापन के तहत आपत्ति नहीं उठा सकते हैं और स्केल-VI तक पदोन्नति करते समय एससी/एसटी कर्मचारियों के पक्ष में आरक्षण से इनकार नहीं कर सकते हैं।

36. उपरोक्त चर्चा का परिणाम इन अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति देना होगा। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को इस सीमा तक रद्द करते हुए कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13-08-1997 आरक्षण का प्रावधान करता है, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में केवल चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। वे पद जिनमें अंतिम वेतन रु. 5,700/- प्रति माह (पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संशोधित करके 18,300/- रुपये और आईडीए पैटर्न का पालन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 20,800/- रुपये प्रति माह)। अपीलकर्ता बैंकों के लिए, जो स्केल-VII और उससे ऊपर के संबंध में होंगे। इसलिए, स्केल-I से स्केल-VI तक पदोन्नति करने के लिए, SC/ST कर्मचारियों के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण देना होगा। इसका असर उत्तरदाताओं/यूनियनों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से अपीलकर्ता बैंकों को स्केल-1 से स्केल-II और स्केल VI तक पदोन्नति करते समय आरक्षण का प्रावधान करने के निर्देशों के साथ अनुमति देने में होगा।

37. उपरोक्त के मद्देनजर, अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 320/2010 को अपीलकर्ता बैंकों को इस निर्णय में उल्लिखित प्रक्रिया को अपनाकर पदोन्नति करने के निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

38. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, हम पार्टियों को उनकी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ते हैं।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गईं और अवमानना याचिका का निपटारा किया गया।

१ (1992) पूरक 3 एस सी सी 217

२ (1995)6 एस सी सी 684

३ (2006)8 एस सी सी 212

४ (1995) 3 एस सी सी 532

५ (2009) 3 एस सी सी 323

६ (2013)10 एस सी सी 308

७ (2014)8 एस सी सी 872

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।